(घ) इस धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) प्रौढ़ शिक्षा तथा ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्षवार तथा राज्य-वार आवंटन नहीं किए जाते हैं। सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम सहित प्रमुख प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं:—

(रु० लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	सातवीं योजना (1985-86 से 1989-90)	वार्षिक योजना (1990-91 तथा 1991-92)	आठवीं योजना (1992-93 से 1996-97)
1.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम	953.51	231.39	—
2.	स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देने की योजना	708.48	245.29	89.32
3.	अतर साक्षरता तथा सतत शिक्षा योजना (जनशिक्षण निलयम)	83.09	280.58	401.85
4.	निरक्षरता उन्मूलन की विशेष परियोजनाएं	—	375.00	1928.85

(ख) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 120 स्वैच्छिक संगठन इस कार्यक्रम से संबद्ध है।

(ग) और (घ) प्रौढ़ शिक्षा योजनाओं के अन्तर्गत संपूर्ण परियोजना अवधि के लिए अनुदान स्वीकृत किया जाता है जो एक वर्ष से तीन वर्ष के लिए अलग-अलग है। यदि वर्ष विशेष में खर्च न की गई कोई राशि शेष बचती है तो उसे योजना के कार्यान्वयन हेतु अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित किया जाता है।

Drought in Karnataka

667. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of Taluka's suffering from severe drought in Karnataka:

(b) the estimated crop loss in these Taluka's;

(c) whether the Central Government have extended relief to Karnataka and have sent a team to assess the damage;

(d) whether Government of Karnataka has submitted memorandum to the Central Government for financial assitance; and

(e) if so, what action has been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) As the South-West Monsoon, 1995 is still in progress, it is too early at this stage to make an assessment of the extent of crop losses and drought conditions, if any, in Karnataka.

(c) to (e) On the basis of rainfall upto 8th July, 1995, Government of karnataka have submitted a Momorandum seeking Central assistance for drought relief measures estimated to cost Rs. 256.00 crores. Subsequently most parts of the state have received widespread rains. Since the situation has improved substantially, the position would have to be reviewed by the State Government. However, two instalments of Central share of Calamity Relief Fund amounting to Rs. 14.81 crores have been released to the State Government for the first two quarters of 1995-96.